

संपादकीय

सरकार में बदलाव का विरल प्रयोग

भारतीय राजनीति में ऐसे मुख्यमंत्रियों की फैहरिस्त छोटी नहीं है, जिनको कार्यकाल के बीच में ही अपना पद छोड़ना पड़ा। मगर गुजरात में जिस तरह से पूरी सरकार का कायाकल्प किया गया है, वैसा उदाहरण विरल ही है। वहाँ भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नई सरकार ने सत्ता तो संभाल ली है, लेकिन यह सवाल अब भी कायम है कि जब आस्त्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को किसी अन्य दल से कोई बड़ी चुनावी नहीं मिलने जा रही है, तब विजय रूपाणी और उनकी पूरी कैबिनेट को सत्ता से बाहर करने का भला क्या मतलब है? संभवतः इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, इस तरह का बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है। जब किसी राज्य का नेतृत्व उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उत्तर रहा होता, तब बिना वक्त गंवाए वह उसे बेदखल करने से परहेज नहीं करते। वह राज्यों में ऐसा नेता चाहते हैं, जिस पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा एतबार हो। फिर, गुजरात तो उनका गृह राज्य है। यहाँ की परिस्थितियों को भला वह कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने कोशिश भी की कि एकाधिक विधायकों को बचा लिया जाए, जिसके कारण भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी में एक दिन की देरी भी हुई, लेकिन वह सफल नहीं हो सकीं। खबर तो यह भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के ज्यादातर वर्तमान विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। यह क्यायस तब लगाए जा रहे हैं, जब हर विधानसभा चुनाव में भाजपा 30-40 फीसदी विधायकों की फिर से चुनावी दावेदारी खारिज करती रही है। दूसरी बाजह, विजय रूपाणी (पूर्व मुख्यमंत्री) के खिलाफ बड़ती नाराजगी हो सकती है। लोगों की उनसे मूलतः दो शिकायतें थीं। एक, वह कोरोना महामारी के दौरान राहत-कार्य का काम सफाई से नहीं कर सके। कोरोना-प्रबंधन में नकारी के कारण राज्य सरकार की कानी किकिरी भी हुई थी। और दूसरी, पटेल समुदाय का छीजता जाता है। मगर यह वर्ग अब पार्टी से छिटकता जा रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और अमित शाह के दली आने के बाद यहाँ एक बड़ा पाटीदार आंदोलन भी हुआ था, जिससे हार्दिक पटेल का उदय हुआ। नतीजतन, 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 100 सीटें भी नहीं पा सकी थी। अब भाजपा यह दिखाना चाहती है कि 2017 बीते दिनों की बात थोड़े ही गई है और वह फिर से 120 सीटें जीतने का मादा रखती है। इसमें नए चेहरे उसकी मदद कर सकते हैं।

मोदी और शाह की जोड़ी बखूबी जान रही है कि राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है। फिर भी ये बदलाव किए गए, क्योंकि वे आगे की सोच रहे हैं। उनका यह प्रयोग यदि सफल रहा, तो कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी यही दांव खेला जा सकता है। हालांकि, मध्य प्रदेश में पिछले साल ऐसी कोशिश हुई भी थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया व कुछ अन्य विधायकों के कांग्रेस छोड़ने के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और भाजपा वहां पिकर से सतारूढ़ हो गई। मगर विकल्पहीनता की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान को ही शपथ दिलाया गया। हालांकि, उनकी 'जयमीन' काफी काट दी गई है। हां, उत्तर प्रदेश जरूर अपवाद है, जहां योगी अदित्यनाथ जैसी मजबूत शाखियत सत्ता में बनी हुई है। उनके खिलाफ भी एकाधिक प्रयास हुए, लेकिन हिंतुत्व का बड़ा चहरा होने और विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े वर्ग की परसंद होने के कारण उनका बाल बांका नहीं हो सका। संभावना यही है कि अगला विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक धूकीवकरण यहां की चुनावी राजनीति की हकीकत है और किसी भी राज्य के चुनाव में योगी अदित्यनाथ को 'स्टार प्रचारक' बनाने की ढेरों गुजारिशें अब भी आती हैं।

हालांकि, चेहरा बदलने की यह शैली नुकसानदेह भी है। अपने जमाने में इंदिरा गांधी भी ऐसे खूब किया करती थीं। अगर किसी राज्य का नेतृत्व ताकतवर होता दिखता, वह उसके झटके से बदल देती थीं। अंततः यह परिपाटी कांग्रेस की कमजोरी साबित हुई और इसका असर हम आज भी देख रहे हैं। हकीकत यही है कि देश की इस ‘ग्रांड ओल्ड पार्टी’ के पास अब कोई मजबूत क्षत्रिय नहीं है, और इसकी पूरी राजनीति बस नेहरू-गांधी परिवार के आसपास सिमट गई है। मोदी-शाह की जोड़ी इतिहास का यह अद्याय शायद ही भूलना चाहिए। राज्यों में मजबूत नेतृत्व भाजपा की ताकत है। फिर चाहे वह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हों, राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, कर्नाटक में येदियुरप्पा, या फिर गुजरात में खुद नंदें मोदी। बावजूद इसके भाजपा ने गुजरात में इसलिए पूरी सरकार बदलने का दाव खेला है, क्योंकि यह रणनीति हाल-फिलहाल में सफल साबित हुई है। उसके विपक्ष में यहां कोई मजबूत दल नहीं है। कांग्रेस को पाटीदार आंदोलन से फायदा मिला था, और वहां उसका नया नेतृत्व उभरने लगा था। अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे, और सफल भी हुए। दलित चेहरा जिग्नेश मेवाणी ने भी परोक्ष रूप से कांग्रेस की मदद की। मगर अब अल्पेश भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं और हार्दिक भी कांग्रेस के ढेरें से बहुत खुश नहीं हैं। रही बात जिग्नेश की, तो वह अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। अहमद पटेल के निधन के बाद तो कांग्रेस की बची-खुची उमीदें भी दम तोड़ी नजर आ रही हैं। रही बात आप आदमी पार्टी की, तो स्थानीय निकाय चुनाव में उसने अपनी ठीक-ठाक ताकत दिखाई है। मगर यहां न तो उसका संगठन जमीन पकड़ सका है और न उसके पास कोई प्रभावी चेहरा है। यह पार्टी अगर मतदाताओं को प्रभावित करती है, तो मुख्यतः कांग्रेस के ही वोट काटेगी। जाहिर है, भाजपा के लिए खूबैद्र सरकार फायदे का सौदा हो सकती है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व को न उभरने देने की रणनीति आने वाले दिनों में उस पर भारी भी पड़ सकती है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को किसी मुगालते से बचना चाहिए।

प्रवीण कुमार सिंह

कश्मीर में समस्या राजनीतिक या संवैधानिक न होकर मजहबी कट्टरपंथ है

कश्मीर घाटी का त्रसद इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता दिख रहा है। जिहादी आतंकी कश्मीर में बचे-खुचे हिंदू और सिखों को निशाना बना रहे हैं। इससे उपजे भय के कारण वे फिर से पलायन के लिए मजबूर हो सकते हैं। गुरुवार को श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में सिख और हिंदू अध्यापकों को चिन्हित कर मौत के घाट उत्तर दिया गया। इससे पहले श्रीनगर के जानेमाने दवा विक्रेता मधुखन लाल बद्र की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। आतंकियों ने दिहाड़ी कमाने वाले एक दलित वीरेंद्र पासवान को भी नहीं बछाए, जो रोज़ी-रोटी के लिए कश्मीर आया था। इसी दिन मोहम्मद शफी लोन की भी इस शक में हत्या की गई कि वह सुरक्षा बलों की मदद करते हैं। यह पहली बार नहीं जब कश्मीर में जिहादियों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा हो। कश्मीरी हिंदूओं को मजहबी आतंकवाद के कारण वहाँ से करीब-करीब छह बार बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा, जिसके बाद उनकी कभी वापसी भी नहीं हो पाई। आखिरी बड़ा पलायन जनवरी 1990 में हुआ था जब एक ओर जिहादी आतंकी कश्मीरी हिंदूओं की चुन-चुनकर हत्या कर रहे थे और उन्मादियों की हथियारबंद भीड़ मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से 'हम क्या चाहते? निजाम-ए-मुस्तफा', 'रलीव, गलीव, चलीव' (धर्म बदल लो, मारे जाओ या भाग जाओ) के एलान से कदमताल करती धूम रही थी। यह वह दौर था जब पाकिस्तानपरस्त जिहादियों ने अफगानिस्तान से तब की महाशक्ति सेवियत संघ को खेड़ा था और कश्मीर में मौजूद इस्लामिक कट्टरपक्षियों और रावलपिंडी में बैठे उनके आकाऊं को लगता था कि आतंक के बल पर अगर सेवियत

मजहबी फासीवाद को कश्मीरियत और 'कंपेजिट कल्चर' जैसे शब्दांभरों से ढका जाता है। किसी आतंकी को हेडमास्टर का बेटा और किसी पथरबाज को बुनकर बताते हैं। हैरानी यही है कि ऐसा बताने वाले लोग कश्मीर के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर चुप हैं। कश्मीरियत रूपी ढकोसले को समय-समय पर मीडिया में बेचने वाले कश्मीरी नेता भी मौन हैं। निदेष गैर-मुस्लिमों की अंतिम यात्राओं से भी नदारद हैं। हाल-फिलहाल अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह अने वाले दियों में सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का ट्रेलर मात्र है। मौजूदा माहौल में कश्मीर में अल्पसंख्यक खजाने तरीके से नहीं रह सकते। अगर समय रहे सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कश्मीर जल्द ही हिंदू-सिख विहीन होगा। हमें समझना होगा कि ऐसे आतंकवाद से तब तक प्रभावी तरह से नहीं निपटा जा सकता जब तक आतंकी और उन्मादी प्रवृत्ति को जन्म देने वाले वैचारिक प्रचार तंत्र पर प्रहार न किया जाए। ऐसा इसलिए, व्यांकी यही तत्र लगातार नए आतंकियों को जन्म देता है और हिंसा समर्थक समाज गढ़ता है। निदेष लोगों की हत्या आतंकियोंके हाथों में मौजूद बटूक और बम नहीं करते, बल्कि उनके दिमाग में भरा गया मजहबी कट्टरपंथ और दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति घृणा का भाव करता है।

टैक्स हेवन समाप्त हों

15 फीसदी ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स बसूले स्ताव पर ऐतिहासिक गई। आयरलैंड, और हंगरी- इन तीनों लोगों को इस प्रस्ताव पर नहीं। गहन बातचीत में कई देशों और अपवाद करने के बाद तीनों देशों और इस प्रस्ताव का आना लागभग तय हो चुका है। 140 देशों में से 136 न समझौते का समर्थन की अगुआई कर रहे हैं। इसीडी (ऑर्गनाइजेशन एमिक कॉ-ऑपरेशन एंड इट) के मुताबिक यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का दृष्टि हिस्सा कवर कर समझौते की अहमियत में है कि इससे पिछले 40 वर्षों भिन्न देशों के बीच जारी करके निवेशकों और लाल कंपनियों को लुभाने का करने में मदद करती रही तमाम बहुराष्ट्रीय अपना मुख्यालय उन देशों हैं जहां टैक्स सबसे कम यह कि ये कारोबार चाहे में भी करें इनके प्रॉफिट हेस्पा उन देशों में शिफ्ट कर जाहं इनका मुख्यालय इन कंपनियों तथा उन लोगों का तो फायदा होता है की तमाम देशों को दीता है। इस स्थिति में नी जरूरत काफी समय की जा रही थी। इस पर भी चल रही थी। महामारी के चलते को वर्चअल मोड में

लाना पड़ा, लेकिन यही कोरोना इस समझौते तक पहुंचने में मददगार भी हुआ। इस दौरान लॉकडाउन के कारण सभी देश बजट पर जबर्दस्त दबाव महसूस कर रहे थे। लिहाजा सबकी कोशिश थी कि इस समझौते पर जल्द से जल्द सहमति हो जाए। ओईसीडी का अनुमान है कि समझौता लागू हो जाने के बाद सालाना 15000 करोड़ डॉलर (करीब 11,27,000 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त राजस्व आएगा। यही नहीं, 12500 करोड़ डॉलर (करीब 940,000 करोड़ रुपये) प्रॉफिट पर टैक्स लगाने का अधिकार उन देशों को शिफ्ट हो जाएगा जहां ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कमाई करती हैं।

निश्चित रूप से ये रकम बड़ी है। फिर भी ऐसा नहीं है कि इस समझौते से हर कोई संतुष्ट ही है। कहा जा रहा है कि कमज़ोर और विकासशील देशों के हित सुरक्षित रखने के लिए और कदम उठाने होंगे।

यह भी कहा जा रहा है कि 15 फीसदी रेट बहुत कम है और इससे टैक्स हेवन समाप्त नहीं होंगे। बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह समझौता सही दिशा में एक ठोस शुरुआत है। अब पहली जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक से और फिर महीने के अंत में रोम में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से स्वीकृति मिलने के बाद अगले साल तक तमाम देश अपने यहां कानून में आवश्यक बदलाव कर लें ताकि 2023 से यह समझौता लागू करने का लक्ष्य पूरा हो सके।

सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध नहीं टूटा तो लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं आगे भी होंगी

सुप्रीम कोर्ट को भी कोई जल्दी
नहीं, क्योंकि वह उस रपट का संज्ञान
लेने की जरूरत नहीं समझ सकता,
जिसमें कृषि कानूनों की समीक्षा की
गई है और वह भी खुद उसकी ओर

से गठित समिति की ओर से।
कोई नहीं जानता कि आगे क्या
होगा, लेकिन इतना तय है कि
आरोपों-प्रत्यारोपों के साथ एक-दूसरे
को दोषी ठहराने का सिलसिला और
तेज होगा। लखीमपुर की घटना के
बाद ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है—
ठीक वैसे ही जैसे लाल किले की

घटना के बाद हुआ था। निसंदेह यह भी तय है कि यदि सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध नहीं दूटा तो लाल किले और लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं आगे भी होंगी। ये घटनाएं और अधिक हिंसक भी हो सकती हैं और माहौल बिगाड़ने के साथ कानून एवं व्यवस्था को चौपौती

देने वाली भी।



हुआ कि एक के बाद एक विपक्षी राजनीतिक दल किसान संगठनों के साथ खुलकर खड़े होने के लिए आगे आते रहे। वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए सरकार को कोसते रहे और किसान संगठनों की पीठ थपथपाते रहे। विपक्षी दलों के किसान संगठनों के साथ खड़े होने से उनके और सरकार के बीच जारी गतिरोध कम होने के बजाय और बढ़ गया। यह गतिरोध कहां तक पहुंच गया है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अभी जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्र पर गए तो राकेश टिकैत ने ट्वीट कर जो बाइडन से भारत सरकार की शिकायत की। और न ही किसान संगठनों का भुगतान देश करता रहा और करता रहेगा, व्योकि लखीं खौफनाक घटना के बाद भी सकते हैं कि दोनों पक्ष बातची आगे आएंगे।

सरकार और किसान संगठन गतिरोध टूट सकता था, यदि सु सकियता और साहस दिखाता, करीब नौ माह बाद यह याद ते संगठन उन कृषि कानूनों के प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, जिनके

A group of people are gathered outdoors under a clear blue sky. In the center, a person wearing a red shirt is holding a flag with green and white horizontal stripes on a wooden pole. To the left, another person in a grey hoodie is holding up a smartphone to take a photo. The scene suggests a public gathering or protest.

, लेकिन उसका शायद आगे भी अपुर खीरी की ऐसे कहीं कोई त करने के लिए र्दि के बीच जारी प्रीम कोट थोड़ी लेकिन उसे तो साया कि किसान खिलाफ धरना-अमल पर उसने

अदालत उनकी मदद के लिए आगे आती है। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।

क्या लाखोंमपुर खोरों की घटना के बाद हालात बदलेंगे? आसार कम हैं, क्योंकि किसान संगठनों की सक्रियता वाले दो प्रमुख राज्यों-पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी दलों के रुख-रवाये से यह साफ़ है कि उनकी दिलचस्पी दूरमें है कि कृषि से कृषि विधानसभा

दिलचस्पा इसमें है कि कम से कम विधानसभा
चुनावों तक किसान संगठनों का आंदोलन जारी
रहा। खुद किसान संगठन भी इसके संकेत दे रहे
हैं। जहाँ किसान संगठनों को इससे मतलब नहीं
कि कृषि कानूनों के अमल पर तो रोक लगा हुई
है, वहीं सरकार इससे चिंतित नहीं दिखती कि यह
रोक कब हटेगी? सुप्रीम कोर्ट को भी कोई जल्दी
नहीं, क्योंकि वह उस रपट का संज्ञान लेने की
जरूरत नहीं समझ रहा, जिसमें कृषि कानूनों की
समीक्षा की गई है और वह भी खुद उसको ओर

से गठित समिति की ओर से।
कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन
इतना तय है कि आरोपें-प्रत्यारोपें के साथ एक-
दूसरे को दोषी ठहराने का सिलसिला और तेज
होगा। लखीमपुर की घटना के बाद ऐसा होता
हुआ दिख भी रहा है-ठीक वैसे ही जैसे लाल
किले की घटना के बाद हुआ था। निस्देह यह
भी तय है कि यदि सरकार और किसान संगठनों
के बीच गतिरोध नहीं टूटा तो लाल किले और
लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं आगे भी होंगी। ये
घटनाएं और अधिक हिंसक भी हो सकती हैं और
माहौल बिगड़ने के साथ कानून एवं व्यवस्था को
चुनौती देने वाली भी।

इस दिवाली अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर करेंगे बड़ा धमाका

5 नवंबर को रिलीज होगी सूर्यवंशी

अभिनेता अक्षय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि उनकी बहुप्रीक्षित फिल्म 'सूर्यवंशी' दुनिया भर में पांच नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राज्य के सिनेमा घरों को 22 अक्टूबर से खोले जाने की घोषणा के बाद निरेशक रोहित शेंझी ने पिछले महीने सोशल मीडिया पर बताया था कि 'सूर्यवंशी' दिवाली के दौरान रिलीज होगी। हालांकि, इसके बाद फिल्म की रिलीज को लेकर किसी तरीख की घोषणा नहीं की गई। कुमार ने सोशल मीडिया पर छोटा सा एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनके साथ अजय देवगन और रणवीर सिंह भी दिख रहे हैं। 'सूर्यवंशी' में ये दोनों अभिनेता महामान भूमिकाएँ नजर आएंगे। एक सिनेमा हॉल के भीतर फिल्माए गए वीडियो में तीनों अभिनेता दर्शकों से दिवाली के दौरान सिनेमाघरों में फिल्म देखने की अपील कर रहे हैं।

कुमार ने कहा, ''क्या आपको यह जगह याद है, जहां आपने कितनी ही भावनाओं को पर्दे पर उमड़ा देखा है। किसी ने नहीं सोचा था कि फिल्मों की तरह हमारे जीवन में भी 'मध्यांतर' आ जाएगा। लेकिन हम लोग वापस आ गए हैं।'' यह फिल्म 24 मार्च, 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसकी रिलीज की तरीख कई बार बदला गई। महामारी के कारण देशभर में सिनेमाघरों को बंद करना पड़ा था। शेंझी की पुलिस अधिकारी पर आधारित यह वीथी फिल्म है। इससे पहले इसी विषय पर वह अजय देवगन के साथ 'सिंघम', 'सिंघम रिटर्न्स' और रणवीर सिंह के साथ 'सिम्बा' बना चुके हैं। 'सूर्यवंशी' में कुमार के साथ करीना कैफ नजर आएंगी। अगामी फिल्म के प्रस्तोता रिलायांस एंटरटेनमेंट हैं और रोहित शेंझी पिछर्स ने धर्मा प्रोडक्शंस एवं केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है।

फिल्म 'खुफिया' में नजर आएंगे बांगलादेशी एक्ट्रेस अजमेरी हक बधौन

प्रतिष्ठित फिल्मकार विशाल भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म 'खुफिया' में बांगलादेशी एक्ट्रेस अजमेरी हक बधौन को लिया है। नेटफिल्म्स पर प्रसारित होने वाली इस फिल्म में तब्बू अली फजल, आशीष विद्यार्थी और वामिका गबी भी नजर आएंगे। यह फिल्म जासूसी रोमांच से भरपूर होगी और यह सत्य घटनाओं व अनिल भूषण के लोकप्रिय जासूसी उपन्यास 'एस्केप टू नोवेयर' पर आधारित है। भारद्वाज ने बाधन को फिल्म में लेने की जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी और इसके साथ ही अभिनेता के साथ अपनी तस्वीर साझा की। बधौन हाल में चर्चित बांगलादेशी फिल्म 'रेहना मरियम नूर' में नजर आए थे।

इन्टू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में दिखेंगे अजय देवगन, कहा- यह बहुत डरावना था



बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'इन्टू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' में दिखेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए शूटिंग करना 'डरावना' अनुभव था क्योंकि अनजान क्षेत्र में 'कुछ भी हो सकता था।' देवगन ने हाल में कार्यक्रम के एक एपिसोड के लिए मालदीव में कार्यक्रम के मेजबान बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग की है। एपिसोड की शूटिंग हिंद महासागर में हुई, जहां शार्क का प्रभुत्व है और प्रतिकूल मौसम है। इसके बाद वे वीरान द्वीप पर चले जाते हैं। कार्यक्रम के लिए आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान देवगन ने कहा कि इस एपिसोड को फिल्माना किसी फिल्म के एक्शन दृश्य की शूटिंग करने जैसा नहीं था। उन्होंने कहा, 'हम फिल्म की शूटिंग की योजना बनाते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, कम से कम मुझे तो नहीं पता था। यह डरावना था लेकिन मजेदार था।' अभिनेता ने कहा, 'यह एक तरह से खतरनाक था। कुछ भी हो सकता था। हम जंगल में थे, अज्ञात क्षेत्र में थे। बेयर को इस बारे में किंवदं भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था।' प्रेस वार्ता में देवगन के साथ ग्रिल्स और डिस्कवरी इक की दक्षिण एशिया की प्रबंधक निदेशक में बनाता थी। ग्रिल्स ने कहा कि एपिसोड की शूटिंग उनकी टीम के लिए उन्मत्तीपूर्ण थी, क्योंकि हमेशा निजें या वीरान द्वीप 'स्वर्ग' नहीं होता है।

सनी, अमीषा के साथ गदर का सीक्लिंग जल्द होगा रिलीज



सनी देओल और अमीषा पठेल 20 साल बाद गदर: एक प्रेम कथा की अगली कड़ी में बड़े पर्दे पर एक साथ वापसी करेंगे, जो 2001 में रिलीज हुई रस्ते ज्यादा कमाई करने वाली ल्यॉकबस्टर फिल्म थी। गदर 2 निर्देशक अनिल शर्मा और जी स्टूडियो भी साथ आएंगे फिल्म में शर्मा के बेटे, अभिनेता उत्कर्ष शर्मा भी हैं, जो गदर-एक प्रेम कथा में देओल और पठेल द्वारा निभाए गए पात्रों के बच्चे के रूप में दिखाई दिए थे। इस फिल्म के जल्द ही रिलीज होने की योजना है, अभी गदर 2 के लॉट को गुप्त रखा गया है। मूल फिल्म ब्रिटिश भारतीय सेना द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी बूटा सिंह और विभाजन की पृथक्खानी के खिलाफ जेनब नाम की एक युवा मुस्लिम महिला के बीच दुखद प्रेम कहानी पर आधारित है।

सनी लियोनी का नया गाना हुआ रिलीज़

बॉलीवुड इंडस्ट्री के महफिल में चार चाँद लगाने वाली सनी लियोनी का नया सॉन्ग 'परदेसी' रिलीज हो गया है। इस सॉन्ग में सनी लियोन कमाल का डांस कर रही है और अपने फैन्स को खूब लुभा रही है।

सॉन्ग को यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। सनी लियोन के इस सॉन्ग में यूजिंक आर्कों का है और लिरिक्स भी आर्कों की ही हैं। इस गाने के रिलीज होते ही यूट्यूब पर फैन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। सनी लियोनी पिछले कुछ दिनों से मेनरस्ट्रीम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर नजर आ रही थीं। उनके फैस उनके अगले काम का इंतजार कर रहे थे, इसी बीच सनी का एक यूजिंक वीडियो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया और अब उम्मीद है कि उनके फैस को उनका यह अंदाज काफी पसद आएगा। सनी लियोनी अपने डास से हमेशा ही लोगों को हैरान करती नजर आई है। गाने में कॉप टॉप और मल्टीकलर स्कर्ट में एक्ट्रेस का अंदाज गाने में चार चाँद लगा रहा है। जब से गाना रिलीज हुआ है तब से उनका ये गाना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसपर फैस जमकर कमेंट कर रहे हैं। सनी लियोनी बॉलीवुड फिल्मों से काफी समय से दूर हैं। वो आखिरी बार ऐस एक्स प्लेयर की सीरीज बुलेट्स में नज़र आई थी। हालांकि वो सीरीज दर्शकों में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। सनी लियोनी आगे के तमिल सिनेमा में अभिनय करती दिखाई देंगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक्ट्रेस की कई फिल्में बैक-टू-बैक बॉक्स



हम दो हमारे दो के गाना बांसुरी में अलग अंदाज में नज़र आए कृति, राजकुमार

ए.आर. रहमान द्वारा रचित ट्रैक, परम सुंदरी से इंटर्सेट सनसनी पैदा करने के बाद कृति फिर धमाल मचाने वापस आ गई है। इस बार उनके साथ राजकुमार राव भी हैं जो अपकमिंग फिल्म हम दो हमारे दो ट्रैक बांसुरी में धमाका करने वाले हैं। सचिन-जिगर द्वारा रचित बांसुरी एक फ्लूट-टैपिंग राग है। कृति, राजकुमार दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री इस गाने को एक ऑडियो ट्रैट जितना ही विजुअल बना रही है। फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो माता-पिता को गोद लेने की एक अंजीब योजना तैयार करता है ताकि वह अपने प्यार से शादी कर सके। इसमें परेश रावल और रत्ना पाटक शाह भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। रचना के बारे में बांसुरी एक जीवन-जिगर ने कहा कि बांसुरी के जादू को देसी बीट्स के फंकी आकर्षण के साथ मिश्रित किया है। यह विचित्र, ताजा और आकर्षक नंबर है। पीयूष-शाजिया द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस ट्रैक की शोली ने लिखा है और इसे असीस कौर, आइपी सिंह, देव नेंगे के साथ-साथ संगीतकार सचिन-जिगर ने गाया है। दिनेश विजन द्वारा निर्मित और अभिषेक जैन द्वारा निर्देशित हम दो हमारे दो डिजिटी प्लस हॉटस्टार पर 29 अक्टूबर को रिलीज के लिए तैयार है।

अपकमिंग फिल्म में हेलेन केलर की भूमिका निभाएंगी एक्ट्रेस मिलिसेंट सिम्मंड्स

अमेरिकी अभिनेता और दिन्यांग कार्यकर्ता मिलिसेंट सिम्मंड्स अपकमिंग फिल्म हेलेन एंड टीचर में हेलेन केलर की भूमिका निभाएंगी, वही राचेल ब्रोसनाहन उनकी शिक्षक ऐनी की भूमिका निभाएंगी। वैराइटी डॉट कॉम के अनुसार, सिम्मंड्स की कारिंग्यांग स्क्रीन पर डीफ के प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मोड है। वर्षों से केलर की कहानी के अधिकांश रूपांतरों में आम तौर पर ऐसे एक्टर शामिल थे, जो बहरे नहीं हैं। इस बीच, ब्रोसनाहन, केलर इसे नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। 1900 के दशक की शुरूआत में, केलर की अशांत समय का अनुसरण करती है, जब उसकी तेजी से बढ़ती विश्वासित और यौवनी डॉट कॉम के अनुसार, केलर की भूमिका निभाएंगी। 1900 के दशक की अंतिम विश्वासित विश्वविद्यालय में केलर के अंशांत समय का अनुसरण करती है, जब उसकी तेजी से बढ़ती विश्वासित और यौवनी डॉट कॉम के अनुसार, केलर की भूमिका निभाएंगी। रेडिलिफ कॉलेज, हार्डर्विंग विश्वविद्यालय में केलर के अंशांत समय का अनुसरण करती है, जब उसकी तेजी से बढ़ती विश्वासित और यौवनी डॉट कॉम के अनुसार, केलर की भूमिका निभाएंगी। रेडिलिफ कॉल

